(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ अलाटियों द्वारा अपने क्वार्टर 'सबलैट' किए गये हैं और वे किरायेदारों से अपने वेतन से होने वाली कटौती से अधिक किराया वसूल करते हैं; यदि हां, तो कितने अलाटियों ने अपने क्वार्टर सबलैट कर रखे हैं ;

(ग) सरकार द्वारा चालू वर्ष में कितने क्वार्टर बनाये जाने का प्रस्ताव है और सरकारी कर्मचारियों की आवास समस्या कब तक हल हो जायेगी ; और

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों को उस समय तक के लिए जब तक उनको क्वार्टर अलाट नहीं हो जाते कम किराये पर मकान दिलाने के लिए कोई कार्यवाही करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) दिल्ली में भवनों के किराये निरन्तर बढ़ रहे हैं किन्तु यह दिल्ली की कोई निराली विशेषता नहीं है और न ही विभिन्न बस्तियों में बढ़ोतरी को असाधारण कहा जा सकता है।

(ख) उन आवंटियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपने क्वार्टरों को उप-किरायेदारी पर दे रखा है और इस सम्बन्ध में अपने वेतन बिलों से कटौतियों की अपेक्षा अधिक किराया वसूल कर रहे हैं, संपदा निदेशालय में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ संपदा निदेशालय के अधिकारियों द्वारा सरकारी बस्तियों के कभी-कभी अचानक निरीक्षणों के अतिरिक्त किसी निवास स्थान विशेष के सम्बन्ध में जब कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो सामान्य पूल में वास की अनधिकृत उप-किरायेदारी के बारे में पूछताछ की जाती है। वे आवंटी जो, अनधिकृत उप-किरायेदारी के दोषी पाये जाते हैं, आवंटन नियमों में निहित उपबन्धों के अनुसार दण्डित किये जाते हैं। 30-6-71 को समाप्त होने वाली पिछली छमाही में अनधिकृत उप-किरायेदारी की 472 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 105 गुमनाम और छद्मनाम की पाई गई तथा उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और 247 शिकायतों की अब भी जांच की जा रही है । 120 शिकायतों की जांच पूरी हो चुकी है, जिनमें से 116 मामलों में उप-किरायेदारी का अभियोग साबित नहीं हो सका और इन मामलों को समाप्त कर दिया गया है, जब कि 4 मामलों में उप-किरायेदारी साबित हो चुकी है और अधिकारियों को सरकारी वास से वंचित कर दिया गया है।

(ग) चालू वर्ष में टाइप I से IV के 2,428 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं ; इनके अतिरिक्त इन टाइपों के 1,088 क्वार्टर पिछले वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर दिए गये थे।

(घ) कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकारी मुद्रणालयों में हिन्दी की छपाई की क्षमता

5287. **श्री सुधाकर पांडे** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकारी मुद्रणालयों में हिन्दी का कितना काम छपाई हेतु लम्बित पड़ा है और कितने वर्षों से छपाई के लिये सबसे पुराना काम लम्बित पड़ा है ; और

(ख) बढ़ते हुए हिन्दी के काम को पूरा करने के लिये सरकारी मुद्रणालयों की क्षमता बढ़ाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) सरकारी मुद्रणालयों की हिन्दी की क्षमता को बढ़ाने के लिए पहले की गई तथा की जाने वाली प्रस्तावित व्यवस्थाएं नीचे दी जाती हैं :—

(i) कोयम्बतूर तथा रिंगरोड प्रेस नई दिल्ली के भारत सरकार के मुद्रणालयों में दूसरी पारी शुरू करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

(ii) एक आई० बी० एम० कम-आफसेट डुप्लीकेटिंग एकक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड नई दिल्ली, में स्थापित किया जा रहा है, जिससे हिन्दी की क्षमता में 100 पृष्ठ प्रतिदिन तक की वृद्धि की आशा है ।

(iii) भारत सरकार मुद्रणालय रिंग रोड, नई दिल्ली के लिए अंग्रेजी-हिन्दी में कम्पोजिंग के लिए 12 लाइनों की-बोर्ड तथा 8 मोनो की-बोर्ड प्राप्त किए जा रहे हैं । इससे लगभग 125 पृष्ठ प्रतिदिन की क्षमता बढ़ जायेगी ।

(iv) फरीदाबाद में लगभग 100 पृष्ठ प्रतिदिन की क्षमता का एक फोटो-लिथो प्रेस लगाने की एक योजना विचाराधीन है ; तथा

(v) नासिक तथा फरीदाबाद के सरकारी मुद्रणालयों में दूसरी पारी के लिए अतिरिक्त स्टाफ की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

12.03 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED CIRCULATION OF FAKE CURRENCY NOTES

SHRI R. BALAKRISHNA PILLAI (Mavelikara) : Sir, I call the attention of the Minister of Finance to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statemen thereon ;

"The reported fake currency notes of various denominations, worth several crores of rupees, bearing the duplicate number of official notes clandestinely put into circulation in the country."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH). Mr. Speaker, Sir, I rise to make a statement on the notice calling my attention to the reported circulation of fake currency notes of various denominations, bearing the same numbers as of the official notes.

This report is apparently based on certain statements made by Acharya J. B. Kriplani in an article published in the Swarajya of the 17th instant. I am sorry to say sir, that such unverified statements should have been circulated which have the effect of undermining the confidence of the people in the currency of the country. Let me state here and now, with all the emphasis at my command, that the statements made in that article about an unauthorised currency circulating alongside the official currency of the country, are baseless and without foundation.

The bogey of a parallel currency seems to have been imagined out of the reports that have appeared from time to time of people having come across two or more notes of the same denomination bearing identical numbers. In all the cases where the notes were available for exmination, it was found that numbers had been forged on genuine notes. There is reason to believe that this is the work of tricksters, who want to impress their victims with their so-called powers. Such instances of duplication, however, are few and far between and in any case, the duplication is from within the genuine notes in circulation. To think that such isolated cases of duplication evidence a substantial circulation of unauthorised currency, is to permit one's imagination to run beyond the bounds of reason.

It has been alleged that the so called fake currency has been printed on genuine bank note paper allegedly smuggled out of the India Security Press. Sir, the strictness of the security measures enforced in the India Security Press as well as at the Secur-